प्रिंसिपल, मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अन्य

बनाम

डॉ. वंदना सिंह और अन्य

21 अगस्त, 1990

[एस.रंगनाथन और के.एन.सैकिया, जे.जे.]

शिक्षा - व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेशः प्रसूति और स्त्री रोग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम - विशेष चिकित्सा महाविद्यालय- संस्थागत उम्मीदवारों के साथ सभी सीटों को भरना - बाहरी उम्मीदवारों पर विचार नहीं करना - प्रभाव - निर्देश जारी।

अकादमिक वर्ष 1989-90 के लिए, अपीलार्थी महाविधालय के पास प्रसूति और स्त्री रोग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 8 सीटें थी। इनमे से, 6 सीटें संस्थागत अभ्यर्थियों के लिए और 2 बाहरी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थी। प्राचार्य ने किसी बाहरी अभ्यर्थी के मामले पर विचार किए बिना संस्थागत अभ्यर्थियों को प्रवेश देकर सभी आठ सीटें भर दीं। बाहरी उम्मीदवारों में से एक ने रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने दो संस्थागत उम्मीदवारों के प्रवेश को रद्द कर दिया, जिन्हें बाहरी उम्मीदवारों के लिए कोटा के तहत प्रवेश दिया गया था, और प्रिंसिपल को याचिकाकर्ता और अन्य बाहरी उम्मीदवारों के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया, जो कानून के अनुसार योग्यता के आधार पर 'ओपन' 25% सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र थे। व्यथित होकर, प्रिंसिपल और दो संस्थागत उम्मीदवार जिनका प्रवेश उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, ने विशेष अनुमति द्वारा इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

अपीलों का निस्तारण करते हुए, अभिनिर्धारित किया :

1. अपीलार्थी महाविद्यालय ने यह विचार रखा कि चूंकि कोई भी अखिल भारतीय उम्मीदवार रेजीडेंसी योजना में अभिनिर्धारित आधार पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए संस्थागत उम्मीदवारों के लिए पूरे 100% को खुला रखना उचित होगा। यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि यह प्रस्ताव किसी दुर्भावना से प्रेरित था। इसमें राज्य का दावा है कि इस कार्रवाई को उसके समक्ष एक मामले में उच्च न्यायालय के फैसले से मंजूरी दी गई है। ऐसा हो सकता है कि यह एकमात्र दृष्टिकोण नहीं है और यह भी विचार करना संभव है कि कॉलेज को इन पदों का विज्ञापन देना चाहिए था और योग्यता के आधार पर बाहरी उम्मीदवारों द्वारा उन्हें भरना चाहिए था। यदि ऐसा है, तो इस तरह के विज्ञापन को उन व्यक्तियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जैसा कि 26 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना में परिकल्पित किया गया था। यह अधिसूचना ऐसे समय में जारी की गई थी जब 25 प्रतिशत सीटों के लिए अखिल भारतीय आरक्षण की अवधारणा इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित नहीं थी। भले ही फिर भी यह माना जाए कि उच्च न्यायालय यह कहना सही था कि बाहरी उम्मीदवार प्रवेश के लिए पात्र थे, वह पात्रता केवल उन लोगों तक सीमित नहीं हो सकती है जिन्होंने पहले से ही थे आवेदन किया बल्कि योग्यताएँ पूरी करने वाले सभी बाहरी उम्मीदवारों के लिए खुला रखा जाना चाहिए। यह प्रक्रिया उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार दो सप्ताह के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है। सभी बाहरी उम्मीदवारों से आवेदन मंगाने और उनका चयन करने के लिए, या तो परीक्षा के आधार पर या अन्यथा, यह एक बहुत लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया होगी। इन सीटों को संस्थागत उम्मीदवारों को देकर रिक्तियों को भरने का निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार और कॉलेज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह केवल एक संक्रमणकालीन अवधि के लिए लिया गया निर्णय है, क्योंकि 1990 के बाद से, प्रवेश को अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर विनियमित किया जाएगा, और ऐसी परीक्षा हर साल सभी

मेडिकल कॉलेजों के लिए भारत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित की जाती है। राज्य सरकार और कॉलेज द्वारा लिया गया निर्णय एक संक्रमणकालीन कठिनाई से निपटने के लिए एक व्यावहारिक निर्णय था और किसी बाहरी उम्मीदवार के अकेले आवेदन के आधार पर इसे परेशान करने का कोई औचित्य नहीं है। [881 ए-एफ]

2. रेजीडेंसी योजना के पैरा 5 की उचित व्याख्या पर संस्थागत उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए पात्रता इन तक सीमित नहीं है - वे जो 22.8.89 पर घरेलू नौकरियों पर थे, लेकिन इन संस्थागत उम्मीदवारों के लिए भी विस्तारित होंगे जो 1.8.87 के बाद से घरेलू नौकरियों में हैं। इन दोनों निर्णयों को एक साथ पढ़ने का परिणाम यह होगा कि संस्थागत सीटों की पूरी 100% को ऐसे सभी आवेदकों में से भरा जाना चाहिए, बशर्ते कि वे किसी अन्य योग्यता को पूरा करते हों और आवश्यकताएँ जो लागू हो सकती हैं। पूर्व में, 75 प्रतिशत सीटों पर छह उम्मीदवारों के प्रवेश के साथ-साथ 25 प्रतिशत सीटों पर दो उम्मीदवारों के प्रवेश उन संस्थागत उम्मीदवारों को छोड़कर किए गए थे जिन्होंने 1.8.87 और 22.8.89 के बीच अपनी घरेलू नौकरी पूरी की थी। इसकी अब पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता होगी। इन फैसलों के आलोक में प्रशासन की पूरी प्रक्रिया को अब फिर से करना होगा। विचाराधीन दो संस्थागत उम्मीदवारों का चयन तभी वैध होगा जब वे इस तरह के पुनर्विचार पर योग्यता के आधार पर सफलतापूर्वक सफल होंगे। उच्च न्यायालय का यह निर्णय सही था कि उनके प्रवेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इन दोनों निर्णयों में टिप्पणियों के आलोक में प्रवेश फिर से किया जाना चाहिए। [882 बी-ई]

डॉ. हरिहर प्रसाद सिंह और अन्य इत्यादि बनाम प्राचार्य, मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अन्य इत्यादि, [1990] 3 एस.सी.आर.895, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 4339-4341/1990

(डब्ल्यू.पी.संख्या 1841/1990 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 30.5.90 से।)

कपिल सिब्बल, सतीश चंद्र, सुश्री शोभा दीक्षित, आर.के. विरमानी और एन. डी. गर्ग, पक्षकारों की ओर से उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय रंगनाथन, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया-

इन तीन याचिकाओं का निस्तारण एक सामान्य आदेश से किया जा सकता है। चूँकि हमने कुछ सीमा तक विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, हम इन याचिकाओं में विशेष अनुमति प्रदान करते हैं और अपीलों के निस्तारण के लिए कारवाही करते हैं।

मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (एम.एल.एन. कॉलेज) इलाहाबाद में प्रसूति और गायनेकोलॉजी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 8 सीटें हैं। इनमें से 6 सीटें संस्थागत उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं और दो बाहरी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। प्रधानाचार्य कॉलेज ने संस्थागत उम्मीदवारों को प्रवेश देकर और बाहरी उम्मीदवारों के मामले पर विचार किया बिना सभी 8 सीटों को भर दिया। संस्थागत उम्मीदवारों में डॉ. जूही जैन और डॉ. पद्मा पंजवानी, जिन्होंने सबसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, को प्रवेश किया गया और डॉ. वंदना सिंह, जिन्होंने प्रवेश के लिए एक बाहरी उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया था, विचार नहीं किया गया। डॉ. वंदना सिंह ने इसलिए अलाहाबाद उच्च न्यायालय को संपर्क किया, जिन्होंने उसके तर्क को माना और निर्धारित किया कि प्रश्नगत दो सीटें राज्य द्वारा 26 अप्रैल, 1986 को प्रकाशित अधिसूचना (पिछली अधिसूचना दिनांकित 15.12.1982 में संशोधन) के अनुसार भरा जाना चाहिए, जो निम्नलिखित रूप में प्रदत्त हैः

" प्रत्येक विशेषज्ञता में, किसी विशेष मेडिकल कॉलेज में पचहत्तर प्रतिशत सीटें उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने उस कॉलेज से एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण की है और शेष पच्चीस प्रतिशत सीटों के मुकाबले, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अन्य मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण की है और योग्य हैं। उत्तर प्रदेश का निवासी, उसी कॉलेज से एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के साथ योग्यता के आधार पर प्रवेश के लिए पात्र होगा।"

इसलिए न्यायालय ने डॉ. जूही जैन और डॉ. पद्मा पंजवानी में प्रवेश को रद्द कर दिया और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को डॉ. वंदना सिंह और अन्य बाहरी उम्मीदवारों के मामलों पर, जो योग्यता के आधार पर और कानून के अनुसार "खुली" पच्चीस प्रतिशत सीटों में प्रवेश के लिए पात्र थे, विचार करने का निर्देश दिया।

मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य, डॉ. जूही जैन और डॉ. पद्मा पंजवानी ने इन अपीलों को प्राथमिकता दी है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस बात की अनदेखी की है कि प्रश्नगत प्रवेश द्वितीय वर्ष या स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में थे और दिनांक 22.8.89 की रेजीडेंसी योजना की शर्तों के तहत विचार किया गया था। इस योजना की शर्तों के अनुसार, पाठ्यक्रम में 25 प्रतिशत सीटें (यहां, दो सीटें) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों द्वारा भरी जानी थीं। हालाँकि, अखिल भारतीय संस्थान द्वारा ऐसी कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी और कॉलेज ने सीटों को खाली छोड़ने के बजाय, योग्यता के आधार पर आंतरिक उम्मीदवारों द्वारा उन्हें भरने का निर्णय लिया। ऐसा करने में, केवल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आर. पी. पांडे के मामले में (रिट याचिका संख्या 8181/1989) इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की शर्तों का पालन कर रहे थे, और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, चिकित्सा परीक्षा प्रकोष्ठ, निर्माण भवन, नई दिल्ली

द्वारा अनुमोदित एक उदाहरण का जिसने आगरा कॉलेज के प्राचार्य को एक पत्र में, एक विशेष पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों की सिफारिश करने में असमर्थ होने पर, इन सीटों को आंतरिक उम्मीदवारों के पक्ष में जारी किया था। डॉ. जूही जैन की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि यह मानते हुए भी कि डॉ. वंदना सिंह के आवेदन पर विचार किया जाना था, उच्च न्यायालय को दो सीटों में से एक में प्रवेश को रद्द करने के लिए खुद को प्रतिबंधित करना चाहिए था और डॉ. जूही जैन के प्रवेश को बरकरार रखना चाहिए था, जिन्होंने डॉ. पद्मा पंजवानी से अधिक अंक प्राप्त किए थे। डॉ. पद्मा पंजवानी की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह मानते हुए भी कि डॉ. वंदना सिंह का आवेदन विचार के योग्य है, राज्य सरकार को एक अतिरिक्त राष्ट्रीय सीट बनाने और तीनों उम्मीदवारों को समायोजित करने का निर्देश देकर तीनों उम्मीदवारों के हितों की रक्षा की जा सकती थी। इस संबंध में मृदुला अवस्थी, [1988] 3 एस.सी.आर. 762 के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर भरोसा किया गया। अंत में, अपीलार्थियों की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि डॉ. वंदना सिंह अधिसूचना दिनांक 26.4.1986 की शर्तों पर भी प्रवेश के लिए पात्र नहीं थीं क्योंकि वह उत्तर प्रदेश की सदभाविक निवासी नहीं थीं। यह कहा गया है कि उन्होंने बिहार राज्य से अपनी एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण की थी और दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लनेरियासराई, बिहार में स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भी प्रवेश लिया था, एक तथ्य जिसे उन्होंने अपनी रिट याचिका में छुपाया था।

हमने आज यूपी राज्य द्वारा शुरू की गई रेजीडेंसी योजना के कार्यान्वयन के लंबित कुछ दाखिलों के संबंध में एक विस्तृत निर्णय पारित किया है। डॉ. हरिहर प्रसाद सिंह और अन्य साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य, [1990] 3 एससीआर 895 (सिविल अपील, संख्या और, उन कारणों से जो बाद में स्पष्ट होंगे, दायर अपीलों के एक बैच में हमारे

फैसले में, वर्तमान अपीलों में निर्णय को उक्त अपीलों में निर्णय के साथ इसमें शामिल मुद्दों की पूर्ण और उचित समझ के लिए पढ़ा जाना होगा। वह अन्य निर्णय रेजीडेंसी योजना के पैराग्राफ 5 की व्याख्या पर आधारित था और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश से भी संबंधित था। इस योजना में कुछ व्यक्तियों के संबंध में पैरा 5 में एक अस्थायी प्रावधान शामिल था जो 1987 और 1989 के बीच गृह अधिकारी थे, अपील के संबंधित बैच ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के दूसरे वर्ष में 75% सीटों से संबंधित विवाद उठाया था जो संस्थागत उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। यहां प्रश्न "बाहरी" उम्मीदवारों के लिए आरक्षित शेष 25% सीटों के संबंध में उठता है। विवाद के मुद्दे को समझने के लिए, हम रेजिडेंसी योजना के उन पहलुओं पर संक्षेप में बात करेंगे, जिन पर ऊपर उल्लिखित अपीलों के बैचों में हमारे पास विचार करने का कोई अवसर नहीं था, लेकिन जो इन अपीलों के प्रयोजनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

दिनांक 22.8.89 की अधिसूचना द्वारा निवास योजना नामक एक योजना शुरू की गई थी, जो अन्य बातों के साथ-साथ औषधीय पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर विशिष्टताओं में प्रवेश के प्रश्न से संबंधित थी। ये अन्य बैचों की तरह मामले भी इस धारणा पर आगे बढ़े हैं कि जहां तक संस्थागत उम्मीदवारों का उल्लेख है, उनमें प्रवेश डॉ. जूही जैन और डॉ. पद्मा पंजवानी जैसे व्यक्तियों को डिग्री पाठ्यक्रम का द्वितीय वर्ष प्रदान किया जा सकता है जिन्होंने एम.बी.बी.एस. डिग्री परीक्षा पूरी की थी, एक वर्ष की इंटर्नशिप की थी और 22.8.89 को उत्तर प्रदेश राज्य में गृह अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। उन मामलों में एक और विवाद था कि क्या वे व्यक्ति भी जो 1.8.1987 के बाद से गृह अधिकारियों के रूप में काम कर रहे थे, इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे और हमने अपने निर्णय से संबंधित अपीलों में इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया है। यह प्रश्न यहाँ तभी प्रासंगिक होगा जब हम यहाँ उच्च

न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं होंगे। इसलिए हम उस मुद्दे को कुछ समय के लिए अलग रखेंगे और बाद में इस पर विचार करेंगे।

योजना के संबंध में विवरण जारी रखने के लिए, इसने उन उम्मीदवारों के तीन वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रावधान किया, जिन्होंने एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण की थी और एक वर्ष का प्रशिक्षण किया था। इन पाठ्यक्रमों में पचहत्तर प्रतिशत प्रवेश प्रवेश परीक्षा के आधार पर संस्थागत उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होना था; शेष पच्चीस प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर भरी जानी थीं। यह प्रावधान देश के विभिन्न हिस्सों में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्देशों के अनुरूप था। इस न्यायालय ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि 75 प्रतिशत सीटें देश भर के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में स्थानीय या संस्थागत उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है, 25 प्रतिशत की शेष अखिल भारतीय आधार पर भरी जानी चाहिए। अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान (एआईआईएमएस) को अखिल भारतीय आधार पर आरक्षित इन सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा आयोजित करने में सक्षम बनाने के लिए इस न्यायालय द्वारा विस्तृत निर्देश भी दिए गए थे। यह योजना स्पष्ट रूप से हर साल एआईआईएमएस द्वारा आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को संदर्भित करती है। वास्तव में ऐसी परीक्षा जनवरी-फरवरी 1989 में एआईआईएमएस द्वारा आयोजित की गई थी और अनुशंसित उम्मीदवारों को तत्कालीन नियमों के अनुसार यूपी के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिया गया था। हालाँकि, खंड 3 (एफ) में प्रावधान है कि, 75% संस्थागत सीटों के लिए, प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षा नए बैच से लागू की जाएगी और इसके लागू होने से पहले रेजीडेंसी योजना में संस्थागत सीटों पर प्रवेश एम.बी.बी.एस. की योग्यता के आधार पर किया जाएगा। हालाँकि, शेष 25% सीटों के संबंध में वह शांत थी। प्रश्न इसलिए उठा;

शेष 25% सीटों के संबंध में क्या किया जाना था। स्थिति से निपटने के लिए, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने 3.10.89 को निम्नलिखित आशय के निर्देश जारी किए:

"चूँकि इस वर्ष 25 प्रतिशत खुली सीटों के बदले बाहरी छात्रों का प्रवेश नहीं होगा, इसलिए इन खुली सीटों को 75 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों के साथ मिलाने के बाद 1982 के पूरक बैच और 1983 के नियमित बैच के छात्रों का प्रवेश उनकी संयुक्त योग्यता सूची बनाकर पूरी 100% सीटों के बदले किया जाना चाहिए।"

तदनुसार, ऐसा लगता है कि तीन वर्षीय स्नातकोत्तर योजना के पहले वर्ष में 100% सीटों पर प्रवेश पूरी तरह से आंतरिक उम्मीदवारों के लिए खोल दिया गया था, प्रवेश एमबीबीएस में उनकी योग्यता के आधार पर तय किए जा रहे थे। इंतिहान। हालाँकि, हम यहाँ उस मुद्दे से चिंतित नहीं हैं।

हम यहाँ रेजीडेंसी योजना के दूसरे वर्ष में प्रवेश के बारे में चिंतित हैं। इस योजना में यूपी में गृह-अधिकारी के रूप में सेवारत व्यक्तियों को रेजीडेंसी योजना के दूसरे वर्ष में समाहित करके उनके समायोजन के लिए पैरा 5 के दूसरे उप-पैरा में प्रावधान किया गया था। प्रावधान निर्धारित किया गया है और अपील के संबद्ध बैचों में हमारे फैसले में इसके निहितार्थों पर विस्तृत चर्चा की गई है और इसे यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि क्या योजना के पैरा 5 का दूसरा उप-पैरा पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष की सभी सीटों को कवर करता है या केवल 75% को। हालाँकि, इसे स्पष्ट रूप से केवल संस्थागत उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 75% सीटों से संबंधित माना जाता है और, चूंकि 25% सीटों के शेष के संबंध में कोई अन्य प्रावधान था, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि उन सीटों को भी केवल संस्थागत उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए। हालांकि, इस बीच, एक विज्ञापन एम.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद के प्राचार्य द्वारा 21.9.89 पर आदेश जारी किया गया था। यह विज्ञापन

केवल संस्थागत उमीदवारों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत सीटों को भरने से संबंधित था। डॉ. वंदना सिंह द्वारा डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन करने के बारे में कोई विज्ञापन नहीं था। इस स्थिति में हमारे सामने इस मामले का निपटारा यह कहकर किया जा सकता है कि डॉ.वंदना सिंह का आवेदन केवल 21 सितंबर, 1989 के विज्ञापन के जवाब में ही माना जा सकता है और इसलिए उस पर विचार नहीं किया जा सकता था। वह वास्तव में एक संस्थागत उम्मीदवार थी और उस आवेदन के आधार पर, अन्य संस्थागत उम्मीदवारों के प्रवेश को चुनौती देने का उसका कोई अधिकार नहीं है। योजना के पैरा 5 के दूसरे उप-पैरा की व्याख्या यह करना भी संभव है कि यह पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष की संपूर्ण सीटों को कवर करता है, न कि केवल 75% को। इस दृष्टि से भी डॉ. वंदना सिंह का आवेदन निरस्त करना पड़ेगा।

हालाँकि, यह तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा है कि पैरा 5 केवल 75% सीटों से संबंधित है, भले ही उनके आवेदन का आधार कुछ भी हो, डॉ. वंदना सिंह को इस बात पर जोर देने का अधिकार है कि इस योजना के तहत 25% सीटें अखिल भारतीय प्रतियोगिता के लिए खोल दी जानी चाहिए और अलग-अलग आधार पर प्रवेश को सही ढंग से रद्द कर दिया जाना चाहिए। यदि हम इस अवधारणा को सही मानते हैं और अधिसूचना की शर्तों का सख्ती से पालन करते हैं, तो प्रवेश अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर होना चाहिए। हालाँकि, 1989-90 के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऐसी किसी परीक्षा के आयोजित होने की तत्काल कोई संभावना नहीं थी। इस स्थिति में, एक संभावित दृष्टिकोण जो उच्च न्यायालय ने लिया है वह यह है कि इन सीटों को बाहरी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए और महाविधालय को अब दिनांक 26.4.86 की अधिसूचना में निहित शर्तों के अनुसार बाहरी उम्मीदवारों को आमंत्रित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। यदि वह अधिसूचना लागू थी और योग्यता के क्रम में उनका चयन करें।

हालाँकि, महाविधालय ने यह विचार किया कि चूंकि योजना में बताए गए आधार पर कोई भी अखिल भारतीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था, इसलिए पूरे 100% को संस्थागत उम्मीदवारों के लिए खुला रखना उचित होगा। यह सुझाव नहीं दिया गया है कि यह प्रस्ताव किसी दुर्भावना से प्रेरित था। दरअसल राज्य का दावा है कि इस कार्रवाई को डॉ. आरपी पांडे के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह हो सकता है कि यह एकमात्र दृष्टिकोण नहीं है और यह भी विचार करना संभव है कि महाविधालय को इन पदों का विज्ञापन देना चाहिए था और योग्यता के आधार पर बाहरी उम्मीदवारों द्वारा उन्हें भरना चाहिए था। अगर ऐसा है तो ऐसा विज्ञापन उन व्यक्तियों को जारी नहीं रखा जा सकता जो यू. पी. के निवासी हैं जैसा कि 26 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना द्वारा परिकल्पित था। यह अधिसूचना ऐसे समय में जारी की गई थी जब 25 प्रतिशत सीटों के लिए अखिल भारतीय आरक्षण की अवधारणा को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। भले ही हम यह मान लें कि उच्च न्यायालय का यह कहना सही था कि बाहरी उम्मीदवार प्रवेश के लिए पात्र थीं, वह पात्रता केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं हो सकती जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया था-वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. वंदना सिंह एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने एम.एल.एन. महाविधालय में पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया था-लेकिन योग्यता को पूरा करने वाले सभी बाहरी उम्मीदवारों के लिए इसे खुला रखा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार यह प्रक्रिया दो सप्ताह के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है। सभी बाहरी उम्मीदवारों से आवेदन के लिए बुलाना और उन्हें चुनना, या तो पूर्व नियुक्ति के आधार पर या अन्यथा, एक बहुत लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया होगी। हमारी राय में, राज्य सरकार और कॉलेज को संस्थागत उम्मीदवारों को भी इन सीटों की पेशकश करके रिक्तियों को भरने का निर्णय लेने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह निर्णय केवल एक संक्रमणकालीन अवधि के

लिए लिया गया है, क्योंकि 1990 के बाद से, प्रवेश को अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर विनियमित किया जाएगा, और इस तरह की परीक्षा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा हर साल भारत के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए आयोजित की जाती है। हमारी राय में, राज्य सरकार और कॉलेज द्वारा लिया गया निर्णय एक संक्रमणकालीन कठिनाई से निपटने के लिए एक व्यावहारिक निर्णय था और एक बाहरी उम्मीदवार के एकल आवेदन के आधार पर इसे परेशान करने का कोई औचित्य नहीं है।

ऊपर बताए गए कारणों से, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने अपने द्वारा दिए गए आधारों पर की गई स्वीकारोक्ति को रद्द करने में गलती की है। हम डॉ. वंदना सिंह के आवेदन की अस्वीकृति को बरकरार रखते हैं। हमने जो विचार किया है, उसमें इस बारे में कोई राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है कि दिनांक 26.4.86 की अधिसूचना के आधार पर भी, डॉ. वंदना सिंह पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार के लिए पात्र हैं या उन्हें राज्य की ओर से डॉ. जूही जैन और डॉ. पद्मा पंजवानी की ओर से आग्रह किये गए कारणों के लिए इस तरह के विचार से अयोग्य घोषित किया जाता हैं।

ऊपर बताए गए कारणों से, हम उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हैं और अभिनिर्धारित करते है कि डॉ. वंदना सिंह का आवेदन कॉलेज द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, हम यह बताना चाहते हैं कि, अपीलों के संबंधित समूह में, हमने योजना के पैरा 5 के उच्च न्यायालय द्वारा उस व्याख्या को बरकरार रखा है और यह अभिनिर्धारित किया है कि संस्थागत उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए पात्रता इन तक ही सीमित नहीं है - वे जो 22.8.89 पर घरेलू नौकरियों पर थे, बल्कि उन संस्थागत उम्मीदवारों के लिए भी विस्तारित होंगे जो 1.8.87 से घरेलू नौकरियों में हैं। एक साथ पढ़े गए इन दो निर्णयों का परिणाम यह होगा कि संपूर्ण 100%

संस्थागत सीटें ऐसे सभी आवेदकों में से भरी जानी चाहिए, बशर्ते कि वे लागू होने वाली किसी भी अन्य योग्यता और आवश्यकताओं को पूरा करते हों। इससे पहले, 75% सीटों पर छह उम्मीदवारों के साथ-साथ डॉ. जूही जैन और डॉ. पद्मा पंजवानी का 25% सीटों पर प्रवेश उन संस्थागत उम्मीदवारों को छोड़कर किया गया था, जिन्होंने 1.8.87 और 22.8.89 के बीच अपनी गृह नौकरियां पूरी कर ली थीं। अब इसकी समीक्षा करने की जरूरत होगी. इन फैसलों के आलोक में अब दाखिले की पूरी प्रक्रिया फिर से करनी होगी। डॉ. जूही जैन और डॉ. पद्मा पंजवानी का चयन तभी मान्य होगा जब वे इस तरह के पुनर्विचार पर योग्यता के आधार पर सफल होंगे। इसलिए, हमें उच्च न्यायालय से सहमत होना होगा कि डॉ. जूही जैन और डॉ. पद्मा पंजवानी के दाखिले भी रद्द कर दिए जाने चाहिए, लेकिन निर्देश दिया जाए कि इन दो निर्णयों में हमारी टिप्पणियों के आलोक में दाखिले फिर से किए जाएं। इन अपीलों का तदनुसार निस्तारण किया जाता है। हालाँकि, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

जी.एन.

अपीलों का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।